

जम्मू और कश्मीर सरकार के व्यय के लिए
अनुपूरक अनुदान मांग

(2019-20)

(1 अप्रैल, 2019-30 अक्टूबर, 2019)

(दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के सा.का.नि 1223 (अ) के तहत राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा से इस उदघोषणा के अनुसरण में संसद में लोक सभा के समक्ष रखी गई)

**SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANT
FOR EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT
OF
JAMMU AND KASHMIR
(2019-20)**

(1st April, 2019-30th October, 2019)

(With Proclamation of President Rule vide G.S.R 1223 (E), dated: 19th December, 2018 laid down before the house of people of the parliament in pursuance of the said proclamation)

अनुपूरक अनुदान मांगे **SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**
अनुदान सं. 10 : विधि विभाग **DEMAND NO 10 : LAW DEPARTMENT**

लाख रु. में **Rs. IN LAKH**

मूल अनुदान ORIGINAL	राजस्व REVENUE	पूंजीगत CAPTIAL	कुल TOTAL
स्वीकृत VOTED	44382.05	8813.65	53195.70
प्रभारित CHARGED	4692.00	0.00	4692.00
अब अपेक्षित अनुपूरक अनुदान SUPPLEMENTARY GRANTS NOW REQUIRED			
स्वीकृत VOTED	20870.40	0.00	20870.40
प्रभारित CHARGED	0.00	0.00	0.00
कुल मूल और अनुपूरक TOTAL ORIGINAL PLUS SUPPLEMENTARY	69944.45	8813.65	78758.10
स्वीकृत VOTED	65252.45	8813.65	74066.10
प्रभारित CHARGED	4692.00	0.00	4692.00

इन अनुपूरक अनुदानों की गणना निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत की जाएगी This Supplementary grants will be accounted for under the following major heads

राजस्व भाग **REVENUE SECTION**

मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD	राजस्व REVENUE	पूंजीगत CAPTIAL	कुल TOTAL
2014 न्याय प्रशासन Administration Of Justice			
स्वीकृत VOTED	312.80	0.00	312.80
प्रभारित CHARGED			
2015 चुनाव Elections			
स्वीकृत VOTED	20557.60	0.00	20557.60
प्रभारित CHARGED			